

प्रेषक,

एल० फैनई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तरांचल, पौड़ी।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक: 17 मार्च, 2005

विषय—

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-120/45(2002)XXVI(AWAS)/2004 दिनांक 21 फरवरी, 2005 के अनुक्रम में यह अवगत कराया जाना है कि पीएमजीवाई योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित कुल परिव्यय रुपये 70.00 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2004-05 में व्यय के लिए ग्रामीण आवास हेतु रु० 10.00 करोड़ का परिव्यय आवंटित है। पूर्व में त्रुटिवश इसे रुपये 3.00 करोड़ प्रदर्शित कर दिया गया था। इस हेतु सुद्धि पत्र संख्या-197/XXVI/2005 दिनांक 01 मार्च, 2005 निर्गत कर दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2004-05 में ग्रामीण आवास हेतु आवंटित परिव्यय रुपये 10.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत रुपये 5.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की जानी है। रुपये 1.50 करोड़ की स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर दी गई है। अतएव भुझा यह जानने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण आवास हेतु आवंटित परिव्यय रुपये 10.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा स्वीकृति हेतु आवरोध धनराशि रुपये 3.50 करोड़ (रुपये तीन करोड़ पचास-लाख मात्र) वाला वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु आपके निर्वहन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सटर्प स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुस्त न करके यथा आवश्यकतानुसार ही दो अथवा तीन किस्तों में ही किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आगणन सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी लांक निर्माण विभाग की दरों पर बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3— उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

4— उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपदवार फौंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरार आपके स्तर से की जायेगी तथा इस्का आवंटन एवं व्यय वर्तमान नियमों/आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

5— उक्त योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

6— उक्त प्रस्तर-2 से 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य परिषद/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए सुव्यवस्थित लक्षा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी। उक्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही दूसरी किस्त अवगुप्त की जायेगी।

- 7- व्यवस्थापकीय योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों को प्रस्तुत किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- 8- करतबे समय बजट में अनुदान, जो मा. स्तर पर ज. स्तर पर, टैक्स/कोटेशन का अनुपालन किया जायेगा।
- 9- दूसरी किस्त तब अनुदान की जायेगी जब प्रथम किस्त द्वारा अनुदान की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय। इस धनराशि का आवंटन पूर्व में अनुदान धनराशि का 80 प्रतिशत तक के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 10- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को यथा समय उपलब्ध कराते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
- 12- इस संकेत में होने वाला व्यवस्थापकीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-07 को अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-00-अनुदानागत-002-अन्य कार्यालय-01-केन्द्रीय अनुदानागत/केन्द्र द्वारा प्रयोज्यता-01-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता को नहीं देखा जायेगा।
- 13- यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या-647/वि०अनु०-3/2004 दिनांक 09 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल० एम०)
अपर सचिव।

संख्या-116 (1)/45(2002)-XXVI / P.M.G.Y. (AWAS) / 2004 तारीख दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखाएवंकदारी, उत्तरांचल, ओबराय नोटर्स विलिडिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- संयुक्त निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आव-व्यय अनुभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2005 के क्रम में।
- 3- निदेशक, (आर०डी०) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
- 5- समस्त वरिष्ठ कार्याधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 8- श्री एल०एम० पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
- 9- वित्त अनुभाग-3 / गार्ड फाईल।

10- एन० आर० ०६०१०, १६०००

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।